

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 12 जून 2014

विषय:-मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-450/2013 के कम में जनपद टिहरी के जखिण्डा नामक स्थान पर उत्तराखण्ड वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, भरसार का परिसर स्थापित किये जाने हेतु कुल 22.145 है० भूमि कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-274/XI-81(2013-14) दि०-21.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रतापनगर के ग्राम म्यूडा मध्ये जखिण्डा की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं०-24 मध्ये श्रेणी 9(3)ड बंजर के खसरा सं०-3105/0.326 है०, 3119/1.850 है०, 3120/0.044 है०, 3137/5.444 है०, 3162/0.509 है०, 3201/0.033 है०, 3207/0.738 है०, 3396/0.178 है०, 3407/1.129 है० कुल खसरा 9 की कुल रकबा 10.251 है० तथा ग्राम खाण्ड मध्ये जखिण्डा की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं०-356 मध्ये श्रेणी 9(3)ड बंजर के खसरा सं०-6937/2.129 है०, 6938/0.776 है०, 6939/0.026 है०, 6940/0.035 है०, 6941/0.058 है०, 6942/0.208 है०, 6943/0.290 है०, 6944/0.245 है०, 6945/0.244 है०, 6946/0.016 है०, 6947/0.030 है०, 6948/0.050 है०, 6949/0.427 है०, 6950/0.065 है०, 6951/0.040 है०, 6952/0.058 है०, 6953/0.064 है०, 6954/0.061 है०, 6955/1.128 है०, 6956/0.075 है०, 6957/1.880 है०, 6958/1.943 है०, 6959/2.129 है०, 6961/0.855 है० कुल खसरा सं० 24 की कुल 11.894 है० इस प्रकार दो ग्रामों के उक्त खसराओं की कुल 22.145 है० अर्थात् 1107.25 नाली भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।





- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)

सचिव।

पृ0प0संख्या- 857 /समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)

उप सचिव।